**भारत सरकार**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

उच्‍चतर शिक्षा विभाग

**राज्‍य सभा**

अतारांकित प्रश्‍न संख्‍या: 401

उत्‍तर देने की तारीख: 13.12.2018

**विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापन हेतु पीएचडी को अनिवार्य बनाया जाना**

401. श्री आर॰ वैद्यलिंगमः

 क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 2021 के बाद से विश्वविद्यालय स्तर पर अध्यापन हेतु पीएचडी को अनिवार्य कर दिया जाएगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जुलाई, 2021 से विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु पीएचडी डिग्री को अनिवार्य कर दिया है;

(ग) क्या सरकार ने विवादपूर्ण शैक्षिक कार्यनिष्पादन सूचक आधारित मूल्यांकन को भी समाप्त कर दिया है; और

(घ) क्या सरकार ने एक सरलीकृत अध्यापक मूल्यांकन ग्रेडिंग प्रणाली की शुरुआत की है और अनुसंधान आउटपुट में सुधार लाने हेतु विश्वविद्यालयों के लिए शैक्षिक/अनुसंधान अंक को जोड़ा है?

**उत्तर**

**मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री**

**(डॉ. सत्य पाल सिंह)**

(क) और (ख): जी, हां। विश्‍वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 18.07.2018 के भारत के राजपत्र में यूजीसी (विश्‍वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्‍य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्‍यूनतम अर्हताएं और उच्‍चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 अधिसूचित किया है। इन विनियमों के अनुसार, दिनांक 01.07.2021 से विश्‍वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों के पद की सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अर्हता पी.एचडी डिग्री होगी।

(ग) और (घ): जी, हां। कॉलेज और विश्‍वविद्यालय के शिक्षकों के निष्‍पादन के मूल्‍यांकन के लिए शैक्षिक निष्‍पादन सूचक (एपीआई) को यूजीसी (विश्‍वविद्यालय और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्‍य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्‍यूनतम अर्हताएं और उच्‍चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय) विनियम, 2018 में नए मूल्‍यांकन मापदंड और प्रविधि से प्रतिस्‍थापित कर दिया गया है। अन्‍य बातों के साथ-साथ, इस नए मूल्‍यांकन मापदंड में शिक्षण- अध्‍ययन और मूल्‍यांकन, शिक्षण और अनुसंधान कार्यकलापों से संबंधित वैयक्तिक विकास, प्रशासनिक सहायता और विद्यार्थियों के शिक्षणेत्‍तर कार्यकलापों में भागीदारी शामिल है। उपर्युक्‍त विनियम यूजीसी की वेबासाइट <https://www.ugc.ac.in/pdfnews/4033931_UGC-Regulation_min_Qualification_Jul2018.pdf> पर उपलब्‍ध हैं।